

मुख्य समाचार :-

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के गया में लगभग 13 हजार करोड़ रुपये लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कहा— सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून लेकर आई है, प्रधानमंत्री पद भी इसमें शामिल।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से वर्ष 2027 में होने वाले कुंभ को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहयोग का अनुरोध किया।
- प्रदेश में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के 196 चिकित्सा अधिकारियों को एस.डी-ए.सी.पी का लाभ मिलेगा।
- उत्तरकाशी जिले के स्यानाचट्टी में बनी अस्थाई झील को खोलने का काम युद्धस्तर पर जारी।

प्रधानमंत्री/परियोजनाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार के गया में लगभग 13 हजार करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये परियोजनाएँ बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति सहित कई क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और वैशाली तथा कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के तहत 12 हजार ग्रामीण लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के अंतर्गत चार हजार से ज्यादा लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह के दौरान प्रतीकात्मक रूप से कुछ लाभार्थियों को चाबियाँ भी सौंपीं। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले ग्यारह वर्षों में देशभर में चार करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक सौ तीसवाँ संविधान संशोधन विधेयक-2025 का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून लेकर आई है और प्रधानमंत्री पद भी इस दायरे में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति को एक नई दिशा दी है।

मुख्यमंत्री मुलाकात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य तीर्थ क्षेत्रों में वर्ष 2027 में होने वाले कुंभ को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास तथा आवास योजनाओं से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के दिशा-निर्देशों के तहत श्वेत-सूचीकरण और रिडीमेबल वाउचर प्रणाली के कारण निजी डेवलपर्स परियोजनाओं में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती चरणबद्ध भुगतान प्रणाली को फिर से लागू करने का अनुरोध किया, ताकि योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार, ऋषिकेश-गंगा, हरिद्वार-गंगा और टनकपुर स्थित शारदा रिवरफ्रंट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने टीएचडीसी की सीएसआर निधि से एक सौ करोड़ रुपए के सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि यह प्रयास न केवल नमामि गंगे कार्यक्रम को बल देगा, बल्कि सतत पर्यटन और स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा देगा। श्री धामी ने ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर में बिजली लाइनों को भूमिगत करने से जुड़ी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को आर.डी.एस.एस योजना के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। साथ ही हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के लिए 315 करोड़ रुपए के समान प्रस्ताव को भी आर.डी.एस.एस योजना में सम्मिलित करते हुए शीघ्र अनुमोदन का अनुरोध किया।

खेल मंत्री

38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम धनराशि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर देहरादून में होने वाले समारोह में प्रदान की जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज देहरादून में आयोजित बैठक में इस समारोह की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को उनकी नगद इनाम धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले 432 खिलाड़ियों और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतने वाले उत्तराखंड के 27 खिलाड़ियों को भी नगद इनाम धनराशि वितरित की जाएगी।

चिकित्सक सौगात

प्रदेश में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के 196 चिकित्सा अधिकारियों को अब एस.डी-ए.सी.पी का लाभ मिलेगा। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारे डॉक्टर, राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। उनके हितों का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एसीपी का लाभ मिलने से चिकित्सकों को न केवल आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि सेवा के प्रति और अधिक समर्पण की भावना भी बढ़ेगी। वहीं, स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर इस लाभ की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

स्यानाचट्टी झील

उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री मार्ग पर स्यानाचट्टी में मलबे से बनी कृत्रिम झील को खोलने के लिए विभिन्न एजेंसियां युद्धस्तर पर काम कर रही हैं। झील का जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन सचिव, विनोद कुमार सुमन को जल निकासी के लिए चैनलाइजेशन और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सुरक्षित स्थानों में ठहराए गए लोगों के साथ ही स्यानाचट्टी के निवासियों के लिए भोजन, रसोई गैस, दवाइयों के साथ ही पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि अभी नदी के एक हिस्से से पानी की निकासी हो रही है। दलदल होने के कारण चैनलाइजेशन करना अभी संभव नहीं हो पाया है। राहत और बचाव दल अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। इस बीच, उत्तरकाशी जिला प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। झील के कारण संभावित खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी प्रशांत आर्य स्यानाचट्टी में मौजूद हैं और हालात पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। आज जिलाधिकारी राफ्ट से झील के दूसरे किनारे पर स्यानाचट्टी के लोगों से वार्ता करने पहुंचे। उन्होंने झील को जल्द खोलने और लोगों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

सचिव बैठक

संस्कृत शिक्षा, जनगणना और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव, दीपक कुमार ने आज पिथौरागढ़ में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने संस्कृत गांव उर्ग और संस्कृत विद्यालय सुवाकोट का निरीक्षण भी किया।

साहसिक यात्रा

पिथौरागढ़ के मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी आज 'प्रोजेक्ट-21' के तहत तिब्बत सीमा से जुड़े सात अंतरराष्ट्रीय दरों की साहसिक यात्रा पर रवाना हुए। कलेक्ट्रेट परिसर से जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और आईटीबीपी 14वीं बटालियन कमांडर आर.बी.एस. कुशवाह ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। डॉ. सैनी ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना, सीमावर्ती क्षेत्रों में संभावनाओं की तलाश करना और वाइब्रेंट विलेज की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

जिलाधिकारी बैठक

बद्रीश संघर्ष समिति के प्रस्तुत ज्ञापन के संबंध में स्थानीय जनता द्वारा उठाई जा रही मांगों को लेकर आज चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने विभिन्न हितधारकों के साथ ज्योतिर्मठ में बैठक की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर इस विषय पर आगामी 29 अगस्त को देहरादून सचिवालय में प्रमुख सचिव, आवास के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी सम्बंधित हितधारक सम्मिलित होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी बैठक में सभी पक्षों की मांगों और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन की मंशा सभी पक्षों को विश्वास में लेकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की है।